महागठबन्धन ने मारी ऐसी पटकी भाजपा की नाव बीच मझधार पलटी

पटना से विशेष प्रतिनिधि

नीतीश कुमार फ़िर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गये। केन्द्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और जीतन राम मांझी को सत्ता की कमान दे दी थी। इसके पीछे इनका यह नैतिक आग्रह था कि बिहार में जद यू को एक तरह से पराजय का सामना करना पड़ा था और इसलिये मुख्यमंत्री के पद पर उनके बने रहने का औचित्य नहीं रह गया। आखिरकार बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तब तक जीतन राम मांझी ने विद्रोह का विगुल फूंक दिया था।

बहरहाल, बिहार विधानसभा चुनाव में भगवां ब्रिगेड की तमाम तिकड़मबाजियों, साजिशों और स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लगभग 30 से ज्यादा रैलियां करने के वावजूद जद यू, राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। मुलायम सिंह द्वारा बीच मझधार लालू-नीतीश का साथ छोड़ने से फ़र्क तो क्या पड़ना था, समाजववादी पार्टी वहां अपना खाता तक नहीं खोल सकी। मोदी, समर्थक अन्य दलों का भी बुरा हाल हुआ। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह द्वारा बीफ़ और गाय के मुद्दे पर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया।

बिहार में भाजपा की हार के मायने बहुत गहरे हैं। इस चुनाव में नरेन्द्र मोदी की साख दांव पर लगी हुई थी। चुनाव नीतिश-लालू बनाम नरेन्द्र मोदी बनकर रह गया। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई प्रधानमंत्री किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आया और उसे मात खानी पड़ी। दरअसल बिहार में भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही थी, नरेन्द्र मोदी और उनके लगुए-भगुए चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि भाजपा का मतलब ही अब नरेन्द्र मोदी हैं। ऐसे में, बिहार में भाजपा की हार निजी तौर पर नरेन्द्र मोदी की हार है और एक तरह से यह उनके प्रति बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता के मनोभाव को दिखाया है। यह एक तरह का जनमत संग्रह है जिसमें नरेन्द्र मोदी

नकार दिये गये हैं, फ़िलहाल बिहार की जनता द्वारा, आने वाले दिनों में अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में भी जनता उन्हें नकारेगी, इसकी पूरी सम्भावना है। इसके पीछे मुख्य कारण नरेन्द्र मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां है जिन्हें वह विकास और अन्य तरह-तरह के जुमलों से छुपाने की कोशिश करते हैं। विकास के नारे और अन्य जुमलों की सच्चाई सामने आ चूकी है। पूरे देश में मोदी सरकार के प्रति असंतोष की आग सुलग रही है, जो समय आने पर भभक पड़ेगी। बिहार में यही संकेत दिया है जिसे मोदी और उनका गुट समझ पाने में असमर्थ है।

यद्यपि भाजपा में मोदी के एकाधिकारवाद के विरुद्ध व्यापक असंतोष है, जिसे आरएसएस अभी दबाने के प्रयास में लगा है, लेकिन भाजपा के भीतर मोदी की सत्ता को चुनौती मिलकर रहेगी। नरेन्द्र मोदी अभी नीरो जैसा व्यहार कर रहे हैं जो जब रोम जल रहा था तब वह बांसुरी बजा रहा था। नरेन्द्र मोदी को इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा, अभी वह भले ही विदेशों के जितने दौरें कर लें, लेकिन अपने भाषणों में बार-बार हिसाब मांगने और हिसाब देने की बात करने वाले मोदी को जनता ऐसा हिसाब देगी जो बिहार में दिया है।

नीतिश कुमार पांचवी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पद सम्भाला है। उनकी छवि हमेशा बेदाग रही है और वे जनता के बीच लोकप्रिय रहे हैं। पिछड़े से लेकर अल्पसंख्यक और अन्य जातियों में भी उनकी स्वीकार्यता हमेशा ही बनी रही। इस बार के चुनाव में वे और भी मजबूत होकर उभरे हैं और नरेन्द्र मोदी को सीधी टक्कड़ में चारो खाने चित्त करने के बाद अब प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार के रूप में भी उन्हें देखा जा रहा है। ऐसे पहले भी प्रधानमंत्री पद के लिये उनके नाम की चर्चा होती रही है।

इस चुनाव में यह भी दिखा कि बिहार में कमण्डल कुछ नहीं है, जो है वह मण्डल है। जब नरेन्द्र मोदी ने लालू प्रसाद के खिलाफ़ मोर्चा खोलते हुए महागठबन्धन की जीत को जंगल राज पार्ट 2 की वापसी बताकर जनता को भयभीत करना चाहा था तो लालू यादव ने इसके जवाब में मण्डल राज पार्ट 2 का नारा दिया जो काफ़ी कामयाब रहा और पिछड़ा यादव, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक एकजुट हो गया। नीतिश को धोखा देकर नरेन्द्र मोदी की शरण में गये जीतन राम मांझी महा दलित वोट बैंक को भी गोलबन्द नहीं कर पाये। दूसरी तरफ़, लालू यादव की पार्टी राजद को विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें मिली। यह दिखलाता है कि बिहार में जातिवादी समीकरणों को नकार कर कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती। अभी जातियों के समर्थन और अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना जिन्दा कर भाजपा कभी भी वहां जीतने की आशा नहीं कर सकती। आरएसएस और भाजपा के लोगों को भली-भांति यह समझ लेना चाहिये कि मुलायम सिंह यादव और लालू-नीतिश में कुछ बुनियादी फ़र्क है। मुलायम के मुकाबले लालू-नीतिश की जनता में पैंठ कहीं ज़्यादा है और इनकी ही नीतियों का परिणाम है कि हज़ार कोशिश करने के बावजूद नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की टीम बिहार में कोई दंगा करा पाने में असफल रही जबकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने लोकसभा चुनाव के पूर्वऔर बाद में भी खूब दंगे भड़काये, दादरी हत्याकाण्ड कराया। आखिर बिहार में साम्प्रदायिक ध्रुविकरण की हर चाल को नाकाम लालू-नीतिश ने ही किया। इससे इनके प्रति जनता के हर तबके का विश्वास बढा।

बिहार विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को भी नया जीवन मिला और अब राष्ट्रीय स्तर पर यह पार्टी एक बार फ़िर से खड़ा होने के लिये पूरा ज़ोर लगायेगी। बिहार चुनाव परिणाम से कांग्रेस में नये उत्साह का संचार हुआ है। बिहार चुनाव की यह भी एक उपलब्धि ही मानी जायेगी कि इसने मरणासन्न दशा में पड़ी कांग्रेस को जीवन दान दिया है।

इस चुनाव में लालू प्रसाद अधिक मजबूत होकर उभरे, जबकि उनके राजनीतिक अन्त की भविष्यवाणियां की जा चुकी थीं। नई सरकार में लालू प्रसाद का एक पुत्र उपमुख्यमंत्री बना है और दूसरे पुत्र को भी मंत्री पद मिला है। राजनीतिक परिवेक्षकों को यह बात कुछ खटक सी रही है। इसकी वजह यह है कि लालू प्रसाद के दोनों पुत्र राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व और पूरी तरह से अनुभवहीन है। चुनाव जीत जाना अलग बात है। लालू यादव को सब्र रखना चाहिये था। उन्हें पुत्र मोह से बचना चाहिये था और इन्हें अभी राजनीतिक अनुभव हासिल करने का मौका देना चाहिये था। अनुभवी और वरिष्ट नेताओं के होते पहली बार विधायक बने एक नौजवान का उपमुख्यमंत्री बनना अटपटा लगता है और इससे जनता में गलत संदेश जाता है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के लड़के को उपमुख्यमंत्री बनाना स्वीकार किया तो निश्चय ही भारी दबाव में किया। और ऐसा करने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं रहा होगा। सिर्फ़ इस वजह से नीतिश कुमार की नई सरकार पर निशाना साधने का मौका विरोधियों को मिल गया है और जनता के जागरूक तबकों में भी इसकी आलोचना हो रही है। यह गठबंधन की राजनीति के लिये सही नहीं है और इसने नीतिश कुमार की स्थिती को कमज़ोर किया है।

केन्द्र में नरेन्द्र मोदी का विकल्प तैयार करने की जो बात लालू प्रसाद ने पहले कही थी, उसके लिये एक बड़ा मोर्चा तैयार हो पाना कैसे सम्भव होगा, अगर लालू प्रसाद पुत्रमोह में धृतराष्ट्र बन जायेंगे? कुनबा-परस्ती की राजनीति के साथ लालू-नीतिश और कांग्रेस के लिये भी राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बन पाना सम्भव नहीं होगा।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 16-30 नवम्बर 2015 का अंक मिला जिसमें समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण लेख पढने को मिले।

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की करारी हार और लालू-नीतीश व कांग्रेस की शानदार जीत के सम्बन्ध में 'बिहार में भाजपा की हार: काठ की हांडी बार-बार नहीं चढती' अत्यंत उपयुक्त लेख है। इस चुनाव को जीतने के लिये मोदी व शाह ने सभी हथकंडे अपनाए जैसे विकास का झूठा नारा, साम्प्रदायिकता का जहर फ़ैलाना, गाय और बीफ़ का मुद्दा, जंगल राज, मीडिया द्वारा मोदी की लोकप्रियता का लगातार ग्राफ़ बढाना, मोदी व शाह द्वारा चुनावी भाषणों में सभी मर्यादाओं का पूरी तरह उल्लंघन और जुमलेबाज़ी करना, मोदी के पिछड़े वर्ग का होने का प्रचार, पिछड़े व दलितों को मिलने वाले आरक्षण के कुछ हिस्से को छीनकर नीतीश व लालू द्वारा अल्पसंख्यकों को देने का खतरा, नीतीश-लालू-कांग्रेस की विजय की सूरत में पाकिस्तान तथा चीन के हावी होने का खतरा आदि। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री द्वारा एक ही राज्य में लगभग 30 रैलियां की गई और लगभग पूरा केन्द्रीय मंत्रीमंडल तथा अमित शाह व अनेक नेता बिहार में डेरा डाले रहे। इन्होंने जनता के प्रमुख मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो जनता ने अपने मुद्दों के आधार पर वोट डाले और बिना भ्रमित हुए नीतीश-लालू-कांग्रेस को विजयी बनाया जिस पर मोदी, शाह, भाजपा, संघ परिवार व मीडिया भौंचक्के रह गए। इन चुनाव परिणामों ने मोदी की लोकप्रियता की वास्तविकता उज़ागर कर दी। वास्तव में मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ़ तो बिहार चुनाव से पहले ही गिरना शुरू हो चुका था।

लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सैनिक छावनी बोर्ड तथा ज़िला पंचायतों के चुनावों में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसको मीडिया ने जान बूझकर नज़रंदाज कर दिया था क्योंकि मीडिया ने तो मोदी की छवि का निर्माण करना था और मोदी को लोकप्रिय नेता के रूप में बनाए रखना था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव की तरह बिहार चुनाव में करारी हार से भाजपा के दिग्गज नेताओं (मोदी, शाह, अरूण जेटली) तथा आरएसएस ने कोई सबक नहीं सीखा है और ना ही भाजपा के मार्गदर्शक मंडल के परामर्श के बावजूद किसी की जिम्मेदारी तय की जा रही है। आशंका है कि हार से निराश होकर आरएसएस देश में साम्प्रदायिक उन्माद व असहिष्णुता फ़ैलाने में और अधिक सक्रिय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के समय मुजफ्फ़रनगर में साम्प्रदायिक दंगे करवाए गए। बिहार चुनाव के दौरान नोएडा (उत्तर प्रदेश) के दादरी में गौ मांस रखने की अफ़वाह पर एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई तथा हरियाणा में पंचायत चुनाव के मद्देनज़र बल्लबगढ के गांव अटाली तथा टीकरी ब्राह्मण गांव (हथीन क्षेत्र) में साम्प्रदायिक उन्माद व तनाव फ़ैलाया गया। गुजरात की तर्ज़ पर संघ परिवार द्वारा कर्नाटक को अपनी प्रयोगशाला बनाया जा रहा है जहां साम्प्रदायिक तनाव व असहिष्णुता का वातावरण बनाने की हर सम्भव कोशिश की जा रही है। इस समय अत्यंत आवश्यक है कि साम्प्रदायिकता व असहिष्णुता का मुकाबला करने के लिए बिहार का महागठबंधन की तर्ज पर एक व्यापक मोर्चे का गठन किया जाए।

मोदी सरकार द्वारा पुलिस व जांच एजेंसियों के अधिकारियों को अपने निर्देशों पर चलने के लिये मजबूर करने की सभी मर्यादाएं ताक पर रखनी शुरू कर दी है। जो अधिकारी उनकी इच्छानुसार कार्य करता है उसे पुरस्कारस्वरूप महत्वपूर्ण पद दे दिया जाता है अथवा उनकी सेवा काल की अवधि बढा दी जाती है। इसका लेख 'पुलिस कमिश्नर काटेंगे-एन आई ए प्रमुख चाटेंगे-कानून-संविधान हुए एकदम फ़ालतू जब भीमसेन बस्सी और शरद कुमार बने पालतू' में पूरा खुलासा किया गया है। वैसे तो ये हथकंडे सभी सत्तारूढ सरकारें अपनाती हैं, परंतु मोदी सरकार द्वारा इस संबंध में सभी कानून व संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया जा रहा है।

स्तम्भ 'खबर दार-गाय की सुनो' के जरिए संघ परिवार द्वारा गाय के मुद्दे पर उनकी कथनी व करनी में अंतर तथा गौ-हत्या व बीफ़ की अफ़वाह पर साम्प्रदायिक उन्माद व तनाव फ़ैलाने का उचित विवेचन किया गया है। मशीनों तथा ट्रैक्टर द्वारा खेती के कारण बैल की उपयोगिता कम हो गई है जिसका प्रतिकूल प्रभाव गाय पर भी पड़ रहा है। एक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार जिन राज्यों में गौ-हत्या पर कानूनी प्रतिबंध है उन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 10 वर्षों में गौ-स्वामियों की संख्या में कमी आई है जिनमें भाजपा शासित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, उत्तराखंड व पंजाब शामिल है। इसके विपरीत जिन राज्यों में पिछले 10 वर्षों के दौरान गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध नहीं है उन राज्यों (बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू व आंध्र प्रदेश) के ग्रामीण क्षेत्रों में गौ-स्वामियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अत: वास्तव में गाय धार्मिक नहीं आर्थिक मुद्दा है।

छात्रों का सर्वांगीण विकास, समाज के विकास व समस्याओं को समझना तथा समाज की आवश्यकतानुसार शिक्षा नीति बनाना सरकार का लक्ष्य होना चाहिये। परंतु इस पूंजीवादी व्यवस्था में शिक्षा के निजीकरण को बढावा दिया जा रहा है तथा शिक्षा को बाजार के हवाले किया जा रहा है जिसमें छात्र पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के कल कारखानों/उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला केवल औज़ार मात्र रह जाएगा। इस शिक्षा व्यवस्था का 'उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढाने की तैयारी' लेख में सटीक विश्लेषण किया गया है। इस शिक्षा व्यवस्था से निकला छात्र पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम नहीं होगा।

स्तम्भ 'तुर्की-ब-तुर्की/बोय पेड़ बबूल के आम कहां से होय, द्वारा बिहार चुनाव में भाजपा की करारी हार के संदर्भ में मोदी-शाह-जेटली पर निशाना साधते हुए आडवाणी, जोशी, सिन्हा व शान्ता कुमार द्वारा दिए गए संयुक्त बयान ''बिहार में जीत पर जो श्रेय लेने वाले थे उन्हें ही अब हार का जबावदेह होना चाहिए'' पर आडवाणी के जबावदेही विचार के बारे में स्वयं आडवाणी की जवाबदेही पर सटीक कटाक्ष किया गया है।

'हरियाणा की चीनी मिलों की आड़ में लूट का बड़ा स्कैंडल' लेख द्वारा चीनी मिल मालिक, बैंक, केन्द्र व राज्य सरकार की लूट में साठगांठ तथा गन्ना उत्पादक किसानों की दुर्दशा व उनके शोषण का पूरा पर्दाफ़ाश किया गया है। शेष अन्य लेख भी उच्च स्तरीय तथा प्रशंसनीय है।

-प्रो. जुगल किशोर गुप्ता